

Daily Current Affairs

Date : 05 July, 2025



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय बाघ संग्रहालय - अलवर
2.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स (राजस्थान) 1. उमा चौधरी 2. अटल प्रगति पथ
3.	सी-फ्लड (C-FLOOD) नामक 'एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली'
4.	वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI)
5.	स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF)
6.	पहला अश्व रोग मुक्त कम्पार्टमेंट
7.	भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME का योगदान
8.	आस्था पूनिया
9.	प्रधानमंत्री की कैरेबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा
10.	ऑपरेशन- MED MAX और ऑपरेशन- MELON
11.	क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव
12.	OPCW की एशिया में पक्षकार देशों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक

-- 1 --

Daily Current Affairs

Date : 05 July, 2025



13.	"3 बाय 35" पहल
14.	ग्लोबल पीस इंडेक्स, 2025
15.	ब्लू नील नदी
16.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. ऑल-इलेक्ट्रिक व्हीकल टेकऑफ़ एण्ड लैंडिंग (eVTOL) 2. देश का पहला फोटोनिक रडार 3. पुद्दुचेरी का परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम 4. "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटीप्रगति 5. सेल का पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय



राजस्थान परिदृश्य

विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय बाघ संग्रहालय – अलवर

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय बाघ संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की।



➔ मुख्य बिंदु :

- इस संग्रहालय में बाघों से संबंधित प्रदर्शनी और व्यापक जानकारीयां उपलब्ध कराई जाएंगी।
- पर्यटकों को एक ही स्थान पर संग्रहालय, चिड़ियाघर और सरिस्का टाइगर रिजर्व का अनुभव प्राप्त हो सकेगा।
- सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली की पहाड़ियों में अलवर जिले में स्थित है।
- इसे वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। बाद में, वर्ष 1978 में इसे बाघ अभयारण्य का दर्जा मिला और यह प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो गया।
- कांकनवाड़ी किला इस रिजर्व के मध्य में बना हुआ है। माना जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने सत्ता संघर्ष के दौरान अपने भाई दारा शिकोह को इसी किले में कैद किया था।
- यहां पांडवों से जुड़े पांडुपोल नामक स्थल पर भगवान हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है।

न्यूज़ इन शॉर्ट्स (राजस्थान)

क्र. सं.	न्यूज़
1.	उमा चौधरी ♦ जोधपुर निवासी उमा चौधरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में जेवलिन थ्रो (भाला फेंक) प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ♦ उमा वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भोपाल में पदस्थापित हैं। 
2.	अटल प्रगति पथ ♦ हाल ही में, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग ₹81.61 करोड़ की लागत से 49.10 किमी. लम्बाई के अटल प्रगति पथों की स्वीकृति प्रदान की। ♦ गौरतलब है कि अब तक ₹574.11 करोड़ की लागत से बनने वाले 700.12 किमी लम्बाई के 269 अटल प्रगति पथों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। ♦ राजस्थान बजट 2024 - 25 में 10,000 से अधिक आबादी वाले गावों में 1 से 3 किलोमीटर लम्बी सड़क के निर्माण एवं गांव की एक मुख्य सड़क को अटल प्रगति पथ के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। 

राष्ट्रीय परिदृश्य

सी-फ्लड (C-FLOOD) नामक 'एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली'

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सी-फ्लड (C-FLOOD) नामक 'एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली' का उद्घाटन किया।

**जल शक्ति मंत्री
सी आर पाटिल
ने सी-फ्लड
बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली
का शुभारंभ किया**



➔ मुख्य बिंदु :

- यह एक एकीकृत जलप्लावन पूर्वानुमान प्रणाली है, जिसे सी-डैक पुणे और केंद्रीय जल आयोग ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
- यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संचालित राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत क्रियान्वित की गई है, जो भारत के बाढ़ प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

सी-फ्लड (C-FLOOD):

- यह वेब-आधारित मंच गांव स्तर तक दो दिन पूर्व बाढ़ का पूर्वानुमान जल स्तर और बाढ़ मानचित्रों के रूप में प्रदान करता है।
- यह विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों के मॉडल आउटपुट को एकीकृत कर एक समग्र प्रणाली और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय-समर्थन उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- वर्तमान में यह महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों को कवर करता है, और भविष्य में अन्य घाटियों को भी जोड़ा जाएगा।
- सी-फ्लड प्लेटफॉर्म उन्नत 2-डी हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग के जरिए बाढ़ परिदृश्यों का अनुकरण करता है। महानदी बेसिन के सिमुलेशन सी-डैक पुणे के NSM आधारित एचपीसी अवसंरचना पर चलाए जाते हैं, जबकि गोदावरी और तापी बेसिन के मॉडल आउटपुट का एकीकरण NRSC द्वारा विकसित एनएचपी मॉडल से किया गया है।

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI)

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (Financial Fraud Risk Indicators - FRI) को अपनी आंतरिक प्रणालियों में एकीकृत करें, ताकि धोखाधड़ी की पहचान, रोकथाम और प्रबंधन में सुधार किया जा सके।



➔ मुख्य बिंदु :

- वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) को दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
- यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) आधारित एकीकरण के माध्यम से बैंकों और दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) के बीच स्वचालित डेटा आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है, जिससे वास्तविक समय (real-time) में कार्रवाई करना संभव होता है।
- डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) एक सुरक्षित ऑनलाइन मंच है, जिसे साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हितधारकों के बीच दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से जुड़ी जानकारी साझा की जाती है, जिससे समय पर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI):

- यह प्रणाली मई, 2025 में दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) द्वारा लॉन्च की गई है।
- यह एक जोखिम-आधारित मूल्यांकन प्रणाली है, जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में मध्यम, उच्च या अत्यधिक जोखिम की श्रेणियों में वर्गीकृत करती है।
- यह प्रणाली विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं:
 - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP),
 - दूरसंचार विभाग का चक्षु मंच (Chakshu Platform),
 - तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा की गई महत्वपूर्ण जानकारी।

बैंकों के लिए लाभ:

- बैंक एवं वित्तीय संस्थान इस प्रणाली के तहत प्रदान किए गए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) का उपयोग रियल टाइम में कर सकते हैं, जिससे वे:
 - संदिग्ध लेन-देन की तुरंत पहचान कर उसे रोक सकते हैं,
 - ग्राहकों को समय पर चेतावनी या अलर्ट जारी कर सकते हैं,
 - तथा संभावित साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, DIU हितधारकों के साथ नियमित रूप से मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची (Mobile Number Reallocation List - MNRL) साझा करता है, जिसमें उन मोबाइल नंबरों का विवरण होता है जो साइबर अपराध में संलिप्तता, पुनः सत्यापन में विफलता अथवा अन्य कारणों से डिस्कनेक्ट किए गए हैं। यह जानकारी बैंकों को जोखिम भरे मोबाइल नंबरों की पहचान में सहायता प्रदान करती है।

स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (Standing Deposit Facility - SDF) तथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (Marginal Standing Facility - MSF) की उपलब्धता के समय में संशोधन किया है।



➔ मुख्य बिंदु :

- यह परिवर्तन मौद्रिक नीति संचालन को अधिक प्रभावी बनाने तथा बैंकों को तरलता प्रबंधन में बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF):

- स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) के अंतर्गत, बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता (Liquidity) को एक दिन की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास जमा कर सकते हैं।
- यह सुविधा बिना किसी प्रतिभूति (Collateral) के कार्य करती है और इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष नकदी को अवशोषित करना है। SDF, मौद्रिक नीति के संचालन में एक प्रमुख साधन के रूप में कार्य करती है।

मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF):

- मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) एक आपातकालीन तरलता सहायता सुविधा है, जिसके तहत बैंक नकदी की कमी की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- इस सुविधा के अंतर्गत, बैंक सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) को गिरवी रखकर RBI से उधार लेते हैं। MSF, बैंकों को अंतिम विकल्प के रूप में तरलता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।

पहला अश्व रोग मुक्त कम्पार्टमेंट

➔ चर्चा में क्यों?

- 3 जुलाई, 2025 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा मान्यता प्राप्त, रिमाउंट वेटेरनरी कॉर्प्स (TVC) केंद्र, मेरठ छावनी, उत्तर प्रदेश में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का अश्व रोग मुक्त कम्पार्टमेंट स्थापित किया गया।



➔ मुख्य बिंदु :

- यह स्वीकृत वैश्विक जैव सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन में भारतीय खेल घोड़ों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही को सक्षम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- EDFC को आधिकारिक रूप से इक्वाइन संक्रामक एनीमिया, इक्वाइन इन्फ्लूएंजा, इक्वाइन पिरोप्लाज़मोसिस, ग्लैंडर्स और सुरा से मुक्त घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत ऐतिहासिक रूप से वर्ष 2014 से अफ्रीकी हॉर्स सिकनेस से मुक्त रहा है।
- यह उपलब्धि पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, रिमाउंट पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, भारतीय घुड़सवारी महासंघ (EFI) और पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समन्वय का परिणाम है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME का योगदान

➔ चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय MSME मंत्री ने 3 जुलाई, 2025 को मुंबई में विद्युत मापन उपकरण डिजाइन संस्थान (IDEMI) और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) कार्यालयों के दौरे और समीक्षा बैठकों के उपरांत मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।



➔ मुख्य बिंदु :

- **भारतीय MSME** : देश की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैं।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30.1 प्रतिशत हिस्सा है।
- देश में विनिर्माण का 35.4 प्रतिशत और निर्यात का 45.73 प्रतिशत हिस्सा है।
- **उद्यम पोर्टल** : 1 जुलाई, 2020 को लॉन्च किया गया।
- MSME के लिए एक निःशुल्क, कागज़ रहित और स्व-घोषित पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है।
- **उद्यम सहायता पोर्टल** : 11 जनवरी, 2023 को लॉन्च किया गया।

MSME वर्गीकरण:

- केंद्र सरकार ने MSME के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश में संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से लागू करने हेतु अधिसूचित किया।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण की नवीन परिभाषा -

उद्यम	निवेश (करोड़ रुपये में)		टर्नओवर (करोड़ रुपये में)	
	वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित
सूक्ष्म उद्यम	1	2.5	5	10
लघु उद्यम	10	25	50	100
मध्यम उद्यम	50	125	250	500

MSME को प्रोत्साहन हेतु सरकार के प्रयास:

- ऋण की अधिक उपलब्धता : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया।
- MSME क्रेडिट कार्ड : उद्यम पोर्टल पर 10 लाख कार्ड जारी।
- स्टार्टअप्स सहायता हेतु 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स।
- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM): केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा।

आस्था पूनिया

➔ चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया नेवल एविएशन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं।



➔ मुख्य बिंदु :

- भारतीय नौसेना ने INS डेगा, विशाखापत्तनम में द्वितीय बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के स्नातक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर आस्था पूनिया को 'विंग्स ऑफ गोल्ड' से सम्मानित किया गया।
- यह नियुक्ति नौसेना विमानन में लैंगिक समावेशन के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

प्रधानमंत्री की कैरेबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा

➔ चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों : घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा के दौरान कैरेबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे।



➔ मुख्य बिंदु :

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से सम्मानित किया।

- प्रधानमंत्री इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता हैं।

मुख्य समझौते:

- भारतीय फार्माकोपिया पर समझौता ज्ञापन (MoU)
- त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (QIPs) के क्रियान्वयन हेतु भारतीय अनुदान सहायता पर समझौता।
- वर्ष 2025 से 2028 तक की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
- खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU)
- कूटनीतिक प्रशिक्षण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU)

- यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज (UWI) में हिंदी एवं भारतीय अध्ययन के दो ICCR पीठों की पुनः स्थापना पर समझौता ज्ञापन (MoU)

प्रधानमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं :

- त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय डायस्पोरा सदस्यों की छठी पीढ़ी तक ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड सुविधा का विस्तार, इससे पहले यह सुविधा चौथी पीढ़ी तक उपलब्ध थी।
- स्वास्थ्य देखभाल में सहायता के लिए बीस हेमोडायलिसिस इकाइयों और दो समुद्री एम्बुलेंस का उपहार।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- त्रिनिदाद और टोबैगो ने भारत के नेतृत्व वाली प्रमुख वैश्विक पहलों; कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (CDRI) तथा ग्लोबल बायोस्फ़ीयर एलायंस (GBA) में शामिल होने की घोषणा की।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (CDRI)

- CDRI को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान लॉन्च किया गया था।
- ये विभिन्न देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय विकास बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों का एक मल्टी-स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य बुनियादी ढांचे के जोखिम प्रबंधन, वित्तपोषण, मानकों और रिकवरी मैकेनिज्म के क्षेत्र में रिसर्च और जानकारी साझा करने को बढ़ावा देना है।
- यह विकास के सभी स्टेज पर देशों को एक-दूसरे के आर्थिक विकास और प्रगति में योगदान करने में एक मंच प्रदान करता है।

ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (GBA)

- G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वर्ष 2023 में भारत की अगुआई में ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (GBA) की स्थापना की गई।
- अमेरिका, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, भारत, इटली, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) इसके प्रारंभिक प्रवर्तक हैं वहीं कनाडा और सिंगापुर को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है।
- इस गठबंधन का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, हितधारकों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के माध्यम से मजबूत मानक निर्धारण और प्रमाणन को आकार देकर जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

ऑपरेशन- MED MAX और ऑपरेशन- MELON

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने दो महत्वपूर्ण अभियान 'ऑपरेशन MED MAX' और 'ऑपरेशन MELON' आरंभ किए।



➔ मुख्य बिंदु :

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 'ऑपरेशन मेलन' के अंतर्गत डार्कनेट के माध्यम से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई के दौरान LSD ब्लॉट्स, केटामाइन और क्रिप्टोकॉरेंसी जैसी अवैध सामग्री जब्त की गई।
- वहीं, 'ऑपरेशन मेड मैक्स' को दवाओं के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकने हेतु विशेष रूप से प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत कई देशों में फैले सिंडिकेट्स की पहचान कर कार्रवाई की गई।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB):

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रमुख ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है।
- इसका गठन 14 नवंबर, 1985 को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act, 1985) के तहत किया गया था।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

मुख्य कार्य और जिम्मेदारियाँ:

- केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए NDPS अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम आदि के तहत विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाइयों का समन्वय।
- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉलों के तहत अवैध मादक पदार्थ व्यापार के खिलाफ कार्रवाई का कार्यान्वयन।
- विदेशी एजेंसियों और संगठनों के साथ सहयोग कर अवैध व्यापार की रोकथाम सुनिश्चित करना।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित मामलों में अन्य मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जब्ती, प्रवृत्तियों का अध्ययन, खुफिया जानकारी साझा करना, और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करना।

क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, वाशिंगटन, डीसी (USA) में क्वाड समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई जिसमें "क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव" को शुरू करने के निर्णय की घोषणा की गई।



➔ मुख्य बिंदु :

- क्वाड समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- विश्वसनीय और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से महत्वपूर्ण खनिज पुनःप्राप्त करने, और प्रसंस्करण में सहयोग को मजबूत करने के लिए यह पहल शुरू की है।
- यह कदम क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन बढ़ाने के लिए क्वाड सहयोग को बढ़ावा देगा।

क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals):

- वे खनिज होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्त्व या यौगिक हैं।
- यह किसी देश की आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी प्रगति और ऊर्जा संक्रमण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जैसे- लिथियम, कोबाल्ट, निकल आदि।
- भारत सरकार ने देश के लिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की है, जिनमें बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस, पोटैश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE), सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम आदि शामिल हैं।
- वर्तमान में भारत इन मिनरल्स की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

OPCW की एशिया में पक्षकार देशों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारत की मेजबानी में रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन (OPCW) की एशिया में राज्य दलों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की तीन दिवसीय 23वीं क्षेत्रीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई।



➔ मुख्य बिंदु :

- बैठक में एशियाई क्षेत्र के 24 देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों ने भाग लिया - भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, चीन, इराक, जापान, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, मलेशिया, वियतनाम, म्यांमार, मालदीव, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, ओमान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, किर्गिस्तान, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात।
- इस बैठक में OPCW और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शांति और निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय केंद्र (UNRCPD) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य:

- रासायनिक हथियार सम्मेलन के प्रावधानों को उचित रूप से लागू करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्राधिकरणों की क्षमता का निर्माण करना।
- विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं।
- वे रासायनिक हथियार सम्मेलन के प्रावधानों को लागू करने में समस्या और संभावित समाधान पर चर्चा करते हैं।
- यह बातचीत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच नेटवर्क को मजबूत करती है।

रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन (OPCW):

- **स्थापना:** 1997 में
- रासायनिक हथियार सम्मेलन के प्रावधानों को लागू करने के लिए 1992 के रासायनिक हथियार सम्मेलन के प्रावधानों के तहत स्थापित।
- यह सम्मेलन दुनिया में रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है।
- **सदस्य:** 193 देशों ने रासायनिक हथियार सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि की है।
- निम्न देशों ने सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं - अंगोला, दक्षिण सूडान, मिस्र और उत्तर कोरिया।
- **मुख्यालय:** द हेग, नीदरलैंड

"3 बाय 35" पहल

➔ चर्चा में क्यों?

- 2 जुलाई, 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की कीमतें बढ़ाने के लिए "3 बाय 35" पहल शुरू की गई।



➔ मुख्य बिंदु :

- **"3 बाय 35" पहल :** 3 बाय 35 पहल तीन उच्च जोखिम वाले उत्पादों यथा तम्बाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय को लक्षित करके गैर-संचारी रोगों (NCD) के वैश्विक बोझ को कम करने के लिए WHO की रणनीति।

लक्ष्य :

- वर्ष 2035 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य कर में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि करना।
- वर्ष 2030 तक NCD मृत्यु दर को एक तिहाई तक कम करना।

Daily Current Affairs

Date : 05 July, 2025



उद्देश्य :

- अस्वास्थ्यकर उत्पादों की खपत को कम करना।
- अगले दशक में वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पन्न करना।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, रोकथाम और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करना।
- SDG गोल 3 को प्राप्त करना।
- अध्ययनों से पता चलता है कि एक बार में 50 प्रतिशत मूल्य वृद्धि से अगले 50 वर्षों में 50 मिलियन असामयिक मौतों को रोका जा सकता है तथा अगले दशक में सार्वजनिक राजस्व में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हो सकती है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

स्वास्थ्य कर :

- वह कर जो लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है, जैसे तंबाकू, शराब आदि।

ग्लोबल पीस इंडेक्स, 2025

➡ चर्चा में क्यों?

- शांति को मापने और इसके आर्थिक मूल्य का आकलन करने वाले दुनिया के अग्रणी थिंक टैंक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) का 19वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया।



➔ मुख्य बिंदु :

- **प्रकाशन** : सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा वर्ष 2007 से प्रकाशित किया जा रहा है।
- **शामिल देश** : 163 देश (विश्व की 99.7 प्रतिशत आबादी)।
- **संकेतक** : 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेतकों के माध्यम से तीन मुख्य क्षेत्रों में शांति स्तर को मापता है-
 - घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की तीव्रता।
 - सामाजिक सुरक्षा।
 - सैन्यीकरण की स्थिति।
- **वैश्विक शांति सूचकांक, 2025**
- **सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र** : पश्चिमी एवं मध्य यूरोप (शीर्ष 10 में से 8)।
- **सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र** : मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका।
- **वैश्विक शांति में गिरावट** :
 - 0.36 प्रतिशत, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की सर्वाधिक गिरावट है।
 - कुल 87 देशों में गिरावट दर्ज की गई है।
- **वैश्विक शांति में सुधार** : 74 देशों में सुधार हुआ है।
- **समग्र GPI रुझान (2008-2023)** : 94 देशों की स्थिति खराब + 66 में सुधार + 1 अपरिवर्तित।
- **शांति असमानता (Peace Inequality)** में 20 वर्षों में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- **अंतरराष्ट्रीयकृत आंतरिक संघर्ष** : वर्ष 2010 के बाद से 175 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

Daily Current Affairs

Date : 05 July, 2025



2025 के शीर्ष 5 सबसे शांत देश :

रैंक	देश	GPI स्कोर
1	आइसलैंड	1.095
2	आयरलैंड	1.260
3	न्यूजीलैंड	1.282
4	ऑस्ट्रिया	1.294
5	स्विट्ज़रलैंड	1.294

2025 के सबसे अशांत 5 देश :

रैंक	देश	GPI स्कोर
163	रूस	3.441
162	यूक्रेन	3.434
161	सूडान	3.323
160	डी.आर. कांगो	3.292

भारत की स्थिति : 0.58% का सुधार हुआ है।

वर्ष	रैंक
2023	126वाँ
2024	116वाँ
2025	115वाँ (GPI स्कोर: 2.229)

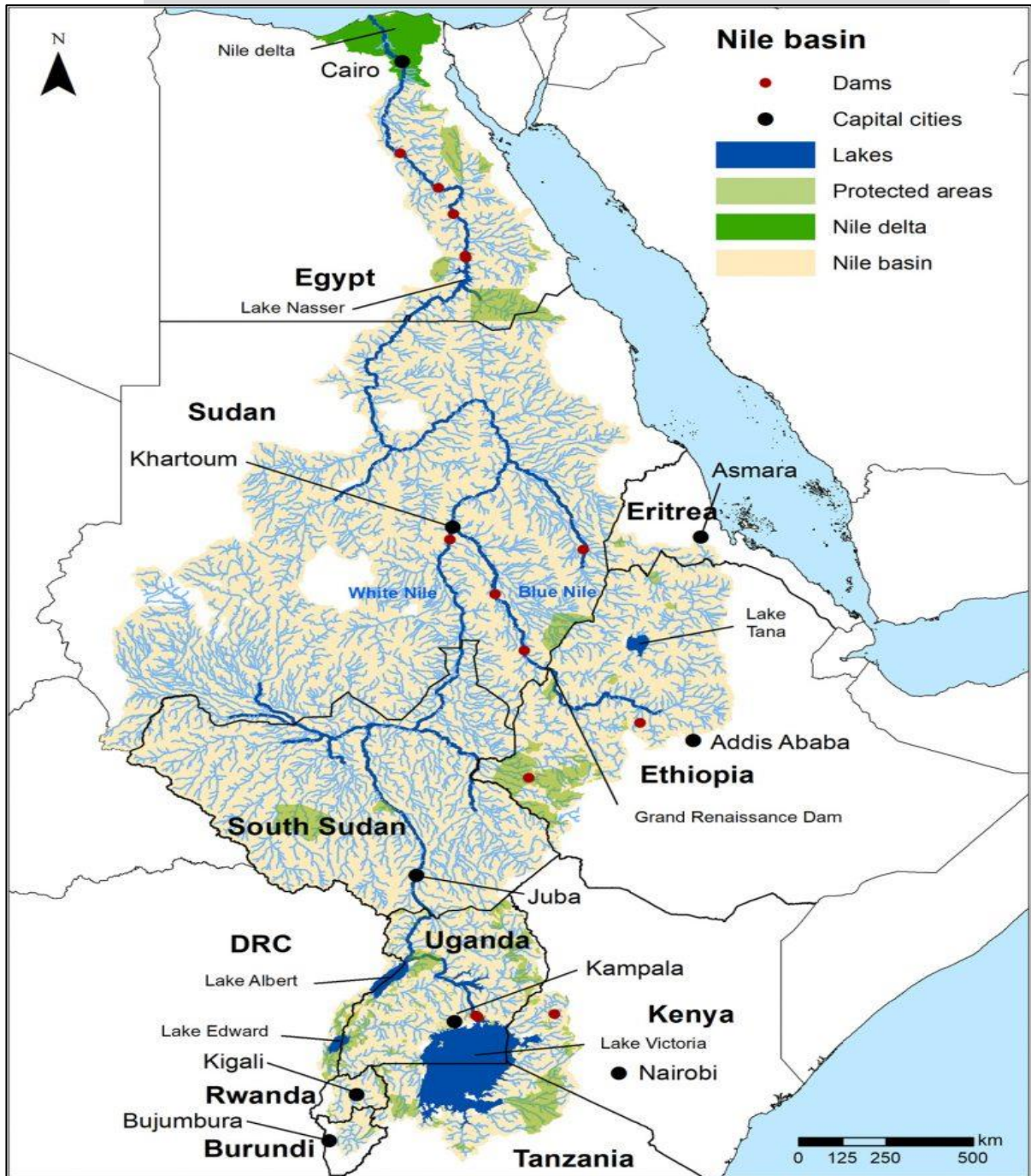
भारत के पड़ोसी देश :

देश	रैंक
बांग्लादेश	123
पाकिस्तान	144
अफगानिस्तान	158

ब्लू नील नदी

➡ चर्चा में क्यों?

- ब्लू नील नदी पर इथियोपिया का ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम (GERD) बनकर तैयार हो गया है।



➔ मुख्य बिंदु :

- इथियोपिया द्वारा 145 मीटर लंबे (475 फुट लंबा) पनबिजली प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू किया गया था।
- यह अफ्रीका की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है।
- इस डैम के निर्माण के चलते मुख्यतः इथियोपिया, मिस्र और सूडान में विवाद हुआ।

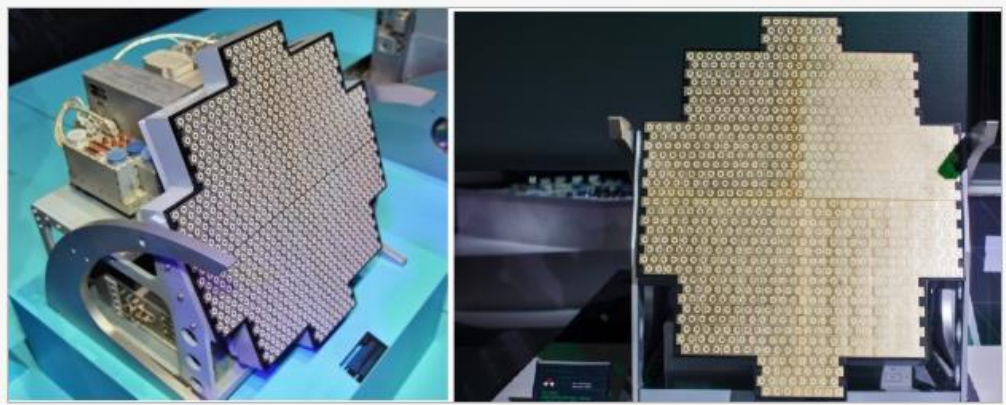
ब्लू नील नदी :

- **उत्पत्ति :** इथियोपिया की ताना झील से ।
- **देश :** इथियोपिया और सूडान।
- **प्रवाह :** सूडान में बहते हुए खार्तुम (Khartoum) में व्हाइट नील से मिलकर नील नदी बनाती है।

नील नदी

- **स्रोत :** यह अफ्रीका में भूमध्यरेखा के दक्षिण में बुरुंडी से निकलकर उत्तर-पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है।
- **दो प्रमुख सहायक नदियाँ :**
 - **व्हाइट नील - उद्गम :** मध्य अफ्रीका के 'महान अफ्रीकी झील' (African Great Lakes) क्षेत्र से होता है।
 - **ब्लू नील - उद्गम :** इथियोपिया की 'लेक ताना' से होता है।
- दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। (लंबाई : लगभग 6,695 किलोमीटर)
- **बेसिन :** तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो और केन्या आदि देशों में स्थित हैं।
- **डेल्टा :** नील नदी एक चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। त्रिकोणीय अथवा धनुषाकार आकार वाले डेल्टा को चापाकार डेल्टा कहा जाता है।

न्यूज़ इन शॉर्ट्स

क्र. सं.	न्यूज़
1.	ऑल-इलेक्ट्रिक व्हीकल टेकऑफ़ एण्ड लैंडिंग (eVTOL)  ♦ हाल ही में, दुबई में ऑल-इलेक्ट्रिक व्हीकल टेकऑफ़ एण्ड लैंडिंग (eVTOL) एयर टैक्सियों की पहली पायलट परीक्षण उड़ान सम्पन्न हुई। ♦ इस एयर टैक्सी का निर्माण जॉबी एविएशन द्वारा किया गया है।
2.	देश का पहला फोटोनिक रडार 

- ♦ हाल ही में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए देश का पहला फोटोनिक रडार विकसित किया है।
- ♦ यह सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए प्रकाश-आधारित घटकों का उपयोग करने वाली एक अत्याधुनिक प्रणाली है।
- ♦ DRDO की यह उपलब्धि भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे अल्ट्रा-हाई रिज़ॉल्यूशन, स्टील्थ (गोपनीय) वस्तुओं की पहचान और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता सुनिश्चित हो सकेगी।

3.

पुडुचेरी का परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम

- ♦ पुडुचेरी भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने TB स्क्रीनिंग को परिवार गोद लेने के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एकीकृत किया है।
- ♦ परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा संचालित एक पहल है, जिसके तहत मेडिकल छात्र अपने सामुदायिक आउटरीच के भाग के रूप में 3 से 5 परिवारों को गोद लेते हैं और उनकी स्क्रीनिंग करते हैं।



4.

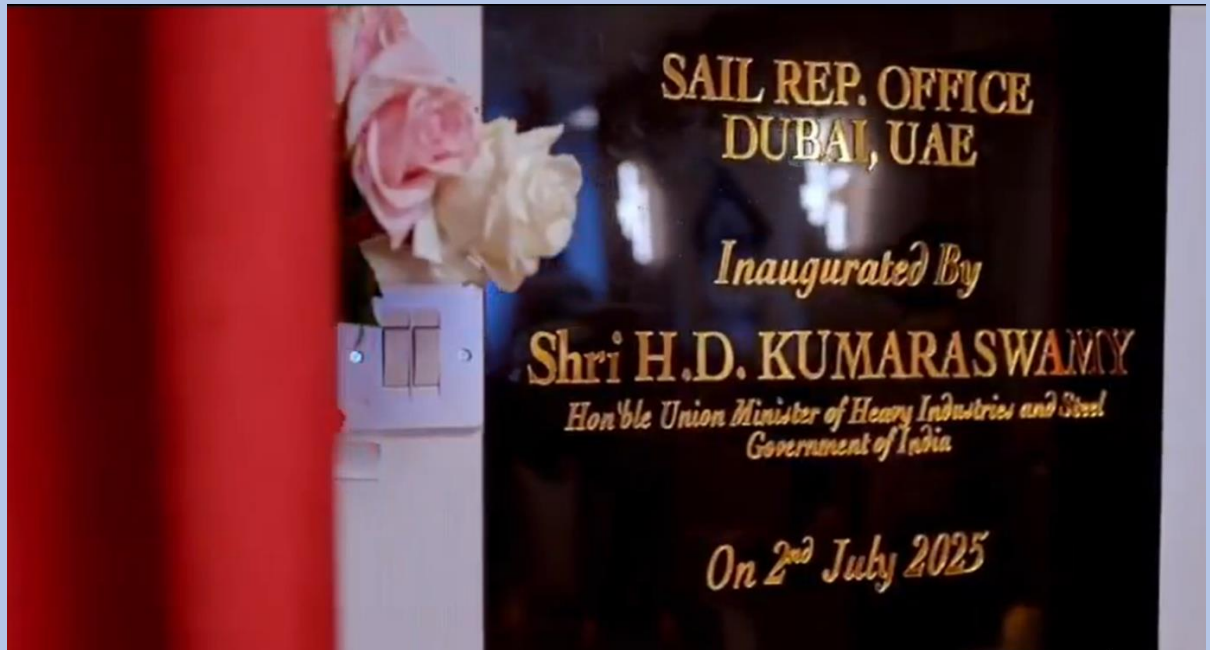
“त्रिभुवन” सहकारी यूनिवर्सिटी

“सहकार से समृद्धि”
सहकारिता मंत्रालय की गौरवपूर्ण चार वर्षीय यात्रा के अवसर पर
“त्रिभुवन” सहकारी यूनिवर्सिटी
का
भूमि पूजन कार्यक्रम
मुख्य अतिथि
श्री अमित शाह
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री,
भारत सरकार
सुबह 11 बजे से
05 जुलाई, 2025
आणंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मैदान,
आणंद, गुजरात

- ♦ 5 जुलाई, 2025 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गुजरात के आणंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय “त्रिभुवन” सहकारी यूनिवर्सिटी (TSU) का भूमि पूजन और शिलान्यास किया।
- ♦ “त्रिभुवन” सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रबंधन, वित्त, कानून और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण श्रमबल और अनुसंधान के अवसर प्रदान करना है।

5.

सेल का पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय



- ◆ भारत के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने दुबई में अपने प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है।
- ◆ मध्य पूर्व में सेल का पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय जो इस्पात निर्यात को बढ़ावा देने, उद्योग संबंधों को मजबूत करने और भारत-UAE व्यापार में सहायता प्रदान करेगा।
- ◆ यह पहल भारत के इस्पात उद्योग की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने और वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन के राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।